



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 फरवरी, 1996/7 फाल्गुन, 1917

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 26 फरवरी, 1996

संख्या 1-19/96-वि० स०. —हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-पंचालन नियमावली, 1973, के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्यांक 9)

जा दिनांक 26 फरवरी, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, एवं सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

के० एल० वर्मा,
सचिव ।

1996 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1996 है।

संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां, जिनका योग 2,49,82,64,255 रुपये (दो अरब, उनचास करोड़, बयासी लाख, चौंसठ हजार और दो सौ पचपन) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1995-96 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए 2,49,82,64,255 रुपये की और राशि जारी करना।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

विनियोग।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं एवं प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा इत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन (राजस्व)	4,50,00,000	—	4,50,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	1,56,50,000	15,10,300	1,71,60,300
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	76,05,000	4,71,000	80,76,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	35,64,19,000	32,34,000	35,96,53,000
	(पूँजी)	14,28,41,000	40,00,000	14,68,41,000
5	भू-राजस्व (राजस्व)	10,01,000	6,32,967	16,33,967
6	आवकारी और कराधान (राजस्व)	24,65,000	—	24,65,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	1,50,16,000	1,50,000	1,51,66,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला (राजस्व)	3,65,70,000	4,25,660	3,69,95,660
	और संस्कृति (पूँजी)	2,50,48,000	—	2,50,48,000
9	चिकित्सा और परिवार (राजस्व)	7,79,000	4,85,467	12,64,467
	कल्याण (पूँजी)	98,26,000	30,422	98,56,422
10	लोक निर्माण (राजस्व)	34,75,00,000	—	34,75,00,000
	(पूँजी)	7,46,99,000	—	7,46,99,000
11	कृषि (राजस्व)	57,03,000	1,08,476	58,11,476
	(पूँजी)	33,00,000	—	33,00,000
12	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व)	36,50,000	—	36,50,000
	नियन्त्रण (पूँजी)	10,000	—	10,000
13	भूमि और जल (राजस्व)	2,80,35,000	—	2,80,35,000
	संरक्षण ।			
14	पशुपालन और दुग्ध (राजस्व)	95,07,000	66,889	95,73,889
	विकास ।			
15	मत्स्य (पूँजी)	30,00,000	—	30,00,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	19,03,000	5,18,869	24,21,869
	(पूँजी)	6,80,000	—	6,80,000

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	39,00,00,000	6,18,575	39,06,18,575
	(पूँजी)	15,08,03,000	2,82,37,643	17,90,40,643
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	1,000	—	1,000
19	सामाजिक सुरक्षा और (राजस्व)	1,01,35,278	7,000	1,01,42,278
	कल्याण (पोषाहार सहित) (पूँजी)	28,14,000	—	28,14,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	17,20,82,000	21,800	17,21,03,800
21	सहकारिता (पूँजी)	55,51,000	—	55,51,000
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	2,000	—	2,000
	(पूँजी)	42,01,000	—	42,01,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण (राजस्व)	1,15,58,500	—	1,15,58,500
	(पूँजी)	83,01,000	—	83,01,000
25	सड़क, जल परिवहन और (पूँजी)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
	नागर विमानन।			
26	पर्वटन और अतिथ्य संगठन (राजस्व)	56,29,000	—	56,29,000
	(पूँजी)	20,39,000	—	20,39,000
28	जलापूर्ति, नफाई, आवास (राजस्व)	23,34,20,000	—	23,34,20,000
	और नगर विकास (पूँजी)	10,96,98,000	2,15,528	10,99,13,528
30	सरकारी कर्मचारियों को (पूँजी)	9,00,00,000	—	9,00,00,000
	ऋण।			
31	जन-जातीय विकास (राजस्व)	1,62,94,000	18,881	1,63,12,881
	(पूँजी)	3,37,75,000	—	3,37,75,000
	कुल जोड़ ..	2,45,75,10,778	4,07,53,477	2,49,82,64,255
	(राजस्व) ..	1,71,59,24,778	82,69,884	1,72,41,94,662
	(पूँजी) ..	74,15,86,000	3,24,83,593	77,40,69,593

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

26 फरवरी, 1996.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल संख्या बित-ए-सी (2)-27/95]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1996 को विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1996.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1996. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 2,49,82,64,255 (Two hundred forty nine crores, eighty two lakhs, sixty four thousand, two hundred and fifty five rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year, 1995-96 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of a further sum of Rs. 2,49,82,64,255, out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year, 1995-96.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Demand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Conso- lidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election (Revenue)	4,50,00,000	—	4,50,00,000
2	Governor and Council of Ministers (Revenue)	1,56,50,000	15,10,300	1,71,60,300
3	Administration of Justice (Revenue)	76,05,000	4,71,000	80,76,000
4	General Administration (Revenue)	35,64,19,000	32,34,000	35,96,53,000
	(Capital)	14,28,41,000	40,00,000	14,68,41,000
5	Land Revenue (Revenue)	10,01,000	6,32,967	16,33,967
6	Excise and Taxation (Revenue)	24,65,000	—	24,65,000
7	Police and Allied Organisations (Revenue)	1,50,16,000	1,50,000	1,51,66,000
8	Education, Sports, Arts and Culture (Revenue)	3,65,70,000	4,25,660	3,69,95,660
	(Capital)	2,50,48,000	—	2,50,48,000
9	Health and Family Welfare (Revenue)	7,79,000	4,85,467	12,64,467
	(Capital)	98,26,000	30,422	98,56,422
10	Public Works (Revenue)	34,75,00,000	—	34,75,00,000
	(Capital)	7,46,99,000	—	7,46,99,000
11	Agriculture (Revenue)	57,03,000	1,08,476	58,11,476
	(Capital)	33,00,000	—	33,00,000
12	Irrigation and Flood Control (Revenue)	36,50,000	—	36,50,000
	(Capital)	10,000	—	10,000
13	Soil and Water Conservation (Revenue)	2,80,35,000	—	2,80,35,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development. (Revenue)	95,07,000	66,889	95,73,889
15	Fisheries (Capital)	30,00,000	—	30,00,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)	19,03,000	5,18,869	24,21,869
	(Capital)	6,80,000	—	6,80,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	39,00,00,000	6,18,575	39,06,18,575
	(Capital)	15,08,03,000	2,82,37,643	17,90,40,643
18	Supplies, Industries and Minerals. (Revenue)	1,000	—	1,000
19	Social Security and Welfare (Revenue)	1,01,35,278	7,000	1,01,42,278
	(Including Nutrition) (Capital)	28,14,000	—	28,14,000
20	Rural Development (Revenue)	17,20,82,000	21,800	17,21,03,800
21	Co-operation (Capital)	55,51,000	—	55,51,000
22	Food and Warehousing (Revenue)	2,000	—	2,000
	(Capital)	42,01,000	—	42,01,000

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
24	Stationery and Printing (Revenue)	1,15,58,500	—	1,15,58,500
	(Capital)	83,01,000	—	83,01,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation. (Capital)	7,50,00,000	—	7,50,00,000
26	Tourism and Hospitality (Revenue)	56,29,000	—	56,29,000
	Organisation (Capital)	20,39,000	—	20,39,000
28	Water Supply, Sanitation, (Revenue)	23,34,20,000	—	23,34,20,000
	Housing and Urban Development (Capital)	10,96,98,000	2,15,528	10,99,13,528
30	Loans to Government Servants (Capital)	9,00,00,000	—	9,00,00,000
31	Tribal Development (Revenue)	1,62,94,000	18,881	1,63,12,881
	(Capital)	3,37,75,000	—	3,37,75,000
	Grand Total ...	2,45,75,10,778	4,07,53,477	2,49,82,64,255
	(Revenue) ..	1,71,59,24,778	82,69,884	1,72,41,94,662
	(Capital) ..	74,15,86,000	3,24,83,593	77,40,69,593

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year, 1995-96.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 26th February, 1996.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department File No. Fin-A-C(2)-27/95]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 1996, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.